बीएसएनएल यूनियन/संघों के फोरम की दूरसंचार विभाग सचिव के साथ, 21-22 अप्रैल की हड़ताल के मुद्दों पर, 1 मई 2015 की आयोजित बैठक की एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

----------01/05/2015

बीएसएनएल यूनियन/ संघों के फोरम की बैठक दूरसंचार विभाग सचिव, श्री राकेश गर्ग के साथ 1 मई 2015 को संचार भवन के समिति कक्ष में आयोजित हुई जिसमे बीएसएनएल कर्मचारियों के दो दिनों की हड़ताल में उठाए गए मुद्दों के बारे में चर्चा हुई।

सचिव दूरसंचार विभाग के अलावा, विशेष सचिव (टी) श्रीमती रीता Teotia, सदस्य (वित्त) श्रीमती एनी मोरेस, सदस्य (सेवाएं) श्री NK Yadav, प्रशासक यूएसओएफ श्रीमती अरुणा Sunderarajan, संयुक्त सचिव (टी) श्री V.Umashankar, निदेशक (पीएसयू) श्री संजीव गुप्ता और अन्य अधिकारी भी दूरसंचार विभाग से उपस्थित थे। बीएसएनएल के सीएमडी श्री अनुपम श्रीवास्तव, प्रवर्तन निदेशालय (वित्त) श्रीमती सुजाता रे, Sr.GM (एसआर) श्री शमीम अख्तर और अन्य अधिकारियो द्वारा प्रतिनिधित्व किया था।

बैठक 17.15 बजे शुरू हुई एव सचिव डॉट का स्वागत किया। सभी प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया। फोरम के संयोजक ने बैठक हड़ताल के तुरंत बाद आयोजित करने के लिए सचिव डॉट को धन्यवाद दिया एवम सभी फोरम की ओर से Coms C.Singh (NFTE) अध्यक्ष, VAN Namboodiri, संयोजक फोरम P.Abhimanyu (BSNLEU), K.Jayaprakash (FNTO), प्रहलाद राय (AIBSNLEA), K.Sebastin (SNEA), SVS Subrahmaniam (BTEU), सुरेश कुमार (BSNLMS), रशीद खान (TEPU), HP Singh (BSNLOA), सुनील गौतम (SNATTA), RP Sahu (AIGETOA), राकेश सेठी (AIBSNLOA), हरि सिंह (BTU बीएसएनएल), राणा प्रताप (बीईए) और S.Raveendran (सेवा बीएसएनएल) ने भाग लिया।

प्रतिभागियों को मई दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने संचार मंत्री के बीएसएनएल के पुनरुद्धार को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में दिये बयान का भी उल्लेख किया जो एक अच्छा संकेत है। इसके बाद हड़ताल के साथ जुड़े मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की गई, जो की रिपोर्ट नीचे दी गई है ।

1. सरकार से वित्तीय सहायता और बीएसएनएल के निगमीकरण के समय दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन ।

फोरम के नेताओं ने बताया कि निगमीकरण के समय पुर्व संचार मंत्री श्री राम विलास पासवान ने नई इकाई के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था और आदेश दिया कि बीएसएनएल को आर्थिक सहायता एडीसी के भुगतान, लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति और यूएसओ फंड की उदार सब्सिडी के माध्यम से दिया जायेगा। कुछ ही वर्षों में, इन सभी को बंद कर दिया गया जिससे भारी वित्तीय

बोझ का निर्माण बीएसएनएल पर हुआ परिणामस्वरूप पिछले पांच साल से नुकसान हुआ। फोरम प्रतिनिधियों ने इन सभी आश्वासनों को कार्यान्वित /बहाल करने की मांग की।

2012-13 के लिए एडीसी के एवज में यूएसओएफ से सिफारिश की 1,250 करोड़ रुपये की राशि अभी तक बीएसएनएल को भुगतान नहीं कि है। यह तत्काल भुगतान किए जाने की जरूरत है और ऐसे आवंटन अगले साल के लिए भी किया जाना चाहिए। बीएसएनएल को ग्रामीण कनेक्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए 10,000 रुपए करोड़ की वार्षिक हानि हो रही है जिसका सरकार की सार्वभौमिक सेवा नीति के अनुसार सरकार द्वारा पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, फोरम ने बीएसएनएल द्वारा बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए दिये शुल्क की वापसी की मांग की जिसका 6,700 करोड़ रुपये अविलम्ब भुगतान बीएसएनएल को किया जाए।

बीएसएनएल, दूरसंचार विभाग को विभीन्न प्रकार से किये भुगतान ध्यान मे रखकर, आयकर की वापसी के लिए पात्र है जो की 7,000 करोड़ रुपये रहा हे। यह वापस किया जाना चाहिए।

अधिकतम वेतनमान के आधार पर पेंशन अंशदान का भुगतान करने के लिए बीएसएनएल को अतिरिक्त 2,400 करोड़ रुपये देने के लिये बाध्य किया गया था। जो की वापस किया जा सकता है। सरकार ने आदेश लागू किया है कि बीएसएनएल के मामले में वास्तविक मूल वेतन पर पेंशन अंशदान का भुगतान होना चाहिए।

TERM CELL के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है, जो दूरसंचार विभाग का हिस्सा है, यह पेसा बीएसएनएल को वापस मिलना चाहिए।

इसके अलावा तत्काल आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए, दूरसंचार विभाग 10,000 करोड़ रुपये का ऋण दे सकता है।

सचिव डॉट ने कहा कि यूएसओएफ से एडीसी के एवज की राशि ट्राई की सिफारिशों के अनुसार दी गयी हे और दूरसंचार विभाग को भी भविष्य में उसी के अनुसार करना होगा । आवंटित 1,250 रुपये करोड़ के भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दि है और जल्दी भुगतान किया जाएगा।

बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम राशी की वापसी पर विचार किया जा रहा है। भुगतान कीये आयकर की वापसी के लिए सुलह शुरू कर दि है और जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन योगदान के भुगतान के मुद्दे को सरकार के सामने उठाया जाएगा। term cell को दिये वेतन के भुगतान की अदायगी के सवाल आदि पर विचार किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपये की सॉफ्ट लोन् के लिए, सचिव डॉट ने कहा कि बीएसएनएल बैंकों से ऋण ले सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को सभी ऑपरेटरों को समान अवसर प्रदान करना होगा जिसमें मंच के नेताओं ने कहा है कि वास्तव में निजी कंपनियों को इष्ट किया जा रहा है जेसे की मोबाइल सेवाओं के मामले में पहले लाइसेंस दिया गया है।

2. बीएसएनएल सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन का Revision और 2007 पूर्व और 2007 के बाद से जून 2013 तक में सेवानिवृत्त लोगों के आईडीए पेंशन 78.2% निर्धारण करने के आदेश :

बीएसएनएल मे जून 2013 तक सेवानिवृत्तो के लिए 78.2% आईडीए पेंशन निर्धारण पर आदेश जारी करने में हुई अनुचित देरी पर मंच के नेताओं ने मजबूत असंतोष व्यक्त किया। जो लोग जून 2013 के बाद सेवानिवृत्त हुए हे उन्हे पहले से यही प्राप्त हुआ हे। पेंशनरों को उनकी पेंशन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हैं पहले से ही ईस साल के लिए देरी हो गई हे और शीघ्र आदेश की आवश्यकता हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि जब भी कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण किया जाना हो वहाँ पेंशन संशोधन भी होना चाहिये। और मांग की कि पेंशन के भुगतान पर 60% -40% की शर्त अनुचित है एवम ईसे दूर किया जाना चाहिए।

सचिव दूरसंचार ने इस मामले को सरकार तक ले जाने का आश्वासन दिया हे एवम आश्वासन दिया कि 78.2% का Cabinet Note तेयार हो रहा हे जिसे जल्द ही अंतीम रूप दिया जाएगा। पेंशन भुगतान पर शर्त के 60% -40% के हटाने के संबंध में, दूरसंचार विभाग के पिछले आदेशो जो फोरम द्वारा उल्लेखीत हे कि जांच की जाएगी।

3. बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय नहीं

फोरम ने मांग की कि किसी भी विलय के निर्णय से पूर्व एमटीएनएल की 20,000 करोड़ रुपये देनदारियों को माफ कीया जाए, विनिवेश शेयर वापस खरीदे जाए ओर मानव संसाधन मुद्दों का निपटारा किया जाये । सचिव डॉट ने कहा कि अभी तक कोइ निर्णय नहीं लिया गया है और फोरम की चिंताओं को किसी भी निर्णय से पूर्व ध्यान मे रखा जायेगा।

4. बीएसएनएल में निदेशक पदों को भरना।

बीएसएनएल में निदेशक पदों को भरने के लिए फोरम की मांग पर् सचिव डॉट ने कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रहा है।

5. बीएसएनएल के लिए सभी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण

फोरम ने बीएसएनएल की सभी परिसंपत्तियों को बिना देरी के उसे स्थानांतरित करने की मांग की। इसके अलावा, प्रतिनिधियों ने कहा कि बीएसएनएल इमारते मनमाने ढंग से सीसीए आदि द्वारा ली जा रही हैं। यह बंद कर दिया जाना चाहिए।

दूरसंचार ने कहा कि डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के बीच सीमांकन अभी भी कुछ स्थानों में लंबित हैं। यह पहचान की जानी है। बीएसएनएल में परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की जांच की जा रही है।

6. बीएसएनएल सेवा केन्द्र / राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनिवार्य करने के लिए :

   बीएसएनएल सेवाओं को अनिवार्य बनाया जाने की फोरम की मांग को सरकारों ने अस्वीकार किया है। बीएसएनएल सेवाओं के बारे में शिकायतों के कारन सरकार द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंच के नेताओं ने वर्तमान अक्षमता की स्थिति के कारणों को समझाया और सुधार के लिए सुझाव दिये

- बीएसएनएल को सेवानिवृत्ति लाभ का 30% अधिकारियों पर, कम वेतनमान भर्ती आदि जैसे अन्य मुद्दों उठाए गए थे, लेकिन सचिव डॉट ने कहा कि यह बीएसएनएल के क्षेत्र में ही है।

- बैठक 19.15 पर समाप्त हुई एवम सभी को धन्यवाद देने के बाद संयोजक व फोरम ने कहा कि एसी बैठक भविष्य मे भी होनी चाहिए जिससे लंबित मुद्दों को सुलझाया जा सके।